Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850
Impact Factor : 2.1506(UIF)
Volume-4 | Issue-10 | Nov-2014
Available online at www.lbp.world

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग (MSME) की भूमिका

डॉ. उमेश कुमार शाक्य
प्रवक्ता अर्थशास्त्र, प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय
जलालाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश (242221).

सारांश (Abstract)

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात संवर्धन तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ बड़ी संख्या में श्रम शक्ति उपलब्ध है, वहाँ MSME क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करता है। यह क्षेत्र भारतीय औद्योगिक संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2013-14 तक भारत में लगभग 4.8 करोड़ MSME इकाइयाँ कार्यरत थीं जो लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रही थीं। यह क्षेत्र कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 45% और निर्यात में लगभग 40% योगदान देता है। यद्यपि इस क्षेत्र के विकास में वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, विपणन समस्याएँ तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी कई चुनौतियाँ भी हैं। यदि सरकार द्वारा इन चुनौतियों का समाधान किया जाए और उचित नीतिगत समर्थन प्रदान किया जाए, तो MSME क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कुंजी शब्द (Keywords) : MSME, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, रोजगार सृजन, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास.

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों का विशेष महत्व है। यह क्षेत्र न केवल औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है बल्कि रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे श्रम प्रधान देश में MSME क्षेत्र कम पूंजी में अधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दौर में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। 2006 में लागू **MSME Development Act** ने इस क्षेत्र को कानूनी और संस्थागत आधार प्रदान किया। MSME क्षेत्र देश के

औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक है।

साहित्य समीक्षा

MSME क्षेत्र पर कई विद्वानों ने अध्ययन किया है।

Schmitz (1995) के अनुसार छोटे उद्योग स्थानीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोजगार सृजन का प्रभावी साधन होते हैं।

Beck और Demirguc-Kunt (2006) ने अपने अध्ययन में पाया कि MSME क्षेत्र आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत के संदर्भ में **Mead और Liedholm (1998)** ने पाया कि छोटे उद्योग विकासशील देशों में रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत होते हैं।

Das (2008) ने भारतीय MSME क्षेत्र का अध्ययन करते हुए बताया कि यह क्षेत्र आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Singh (2012) के अनुसार MSME क्षेत्र ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक है।

MSME Ministry Report (2014) के अनुसार भारत में MSME क्षेत्र लगभग 3.6 करोड़ इकाइयों का समूह है जो करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है ।

Planning Commission (2013) की रिपोर्ट में बताया गया कि MSME क्षेत्र भारत के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत योगदान करता है।

RBI (2013) की रिपोर्ट के अनुसार MSME क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ापन तथा विपणन समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ।

कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि MSME क्षेत्र निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Kumar (2011) के अनुसार भारतीय निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है।

इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

शोध का उद्देश्य

शोध का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण करना, रोजगार सृजन में MSME क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन करना एवं निर्यात और औद्योगिक उत्पादन में MSME क्षेत्र के योगदान का मूल्यांकन करना है।

अनुसंधान परिकल्पनाएँ (Research Hypotheses)

- MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है।
- MSME क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- MSME क्षेत्र निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन **विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध पद्धति** पर आधारित है।

डेटा के स्रोत

शोध हेतु MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, योजना आयोग की रिपोर्ट, RBI रिपोर्ट आदि विभिन्न द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

भारत में MSME इकाइयों की संख्या

वर्ष	इकाइयाँ (करोड़)
2006	3.61
2008	4.10
2010	4.65
2012	4.80
2013	4.85

Source: Ministry of MSME, Government of India, Annual Report 2013-14.

तालिका से स्पष्ट है कि MSME इकाइयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

MSME क्षेत्र द्वारा रोजगार सृजन

वर्ष	रोजगार (करोड़)
2006	8.05
2008	8.75
2010	9.45
2012	9.90
2013	10.10

Source: Fourth All India Census of MSMEs, Ministry of MSME.

रोजगार के आँकड़े दर्शाते हैं कि MSME क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और यह क्षेत्र रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है।

GDP में MSME का योगदान

वर्ष	GDP में योगदान (%)
2006	35
2008	36
2010	37

वर्ष	GDP में योगदान (%)
2012	37.5
2013	38

Source: Economic Survey 2013-14, Government of India.

GDP में MSME का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को दर्शाता है।

भारत के निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान

वर्ष	निर्यात (%)
2006	39
2008	40
2010	41
2012	40
2013	42

Source: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).

लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों की समस्याएँ

भारत की अर्थव्यवस्था में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, क्षेत्रीय संतुलित विकास तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद MSME क्षेत्र कई संरचनात्मक एवं संचालन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है, जो इसके समुचित विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ निम्नवत हैं -

- सबसे प्रमुख समस्या **वित्तीय संसाधनों की कमी** है। अधिकांश MSME इकाइयों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। बैंक और वित्तीय संस्थाएँ अक्सर इन उद्योगों को जोखिमपूर्ण मानते हैं, जिसके कारण उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली होती है, जिससे छोटे उद्यमियों को परेशानी होती है।
- दूसरी महत्वपूर्ण समस्या **प्रौद्योगिकी का अभाव** है। कई लघु और कुटीर उद्योग अभी भी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता सीमित रहती है। वैश्वीकरण के दौर में जब प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, तब आधुनिक तकनीक का अभाव इन उद्योगों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई पैदा करता है।
- तीसरी समस्या **कच्चे माल की उपलब्धता और लागत** से जुड़ी है। कई MSME इकाइयों को कच्चा माल समय पर और उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं हो पाता। बड़ी कंपनियों की तुलना में इन उद्योगों की खरीद शक्ति कम होती है, जिसके कारण उन्हें कच्चे माल की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

- **बाजार और विपणन की समस्या** भी MSME क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश छोटे उद्योगों के पास अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विपणन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। परिणामस्वरूप उनके उत्पाद बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।
- इसके अतिरिक्त **प्रबंधन कौशल और प्रशिक्षण की कमी** भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई उद्यमियों के पास तकनीकी ज्ञान तो होता है, लेकिन आधुनिक प्रबंधन, वित्तीय योजना और विपणन रणनीतियों की जानकारी सीमित होती है। इससे उद्योग की दक्षता और विकास प्रभावित होता है।
- अंततः **अवसंरचना की कमी** भी MSME क्षेत्र के विकास में बाधा बनती है। बिजली, परिवहन, संचार तथा औद्योगिक सुविधाओं का अभाव विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है।

स्पष्ट है कि वित्त, तकनीक, बाजार, प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित समस्याएँ MSME क्षेत्र के समुचित विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं।

सुझाव

- MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इसलिए इसके विकास के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थानों और उद्यमियों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
- सबसे पहले **वित्तीय सहायता को सुलभ और सरल बनाया जाना चाहिए**। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को MSME इकाइयों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि छोटे उद्यमियों को आसानी से पूंजी उपलब्ध हो सके।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन (Technology Upgradation)** से संबंधित है। MSME इकाइयों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। तकनीकी उन्नयन से उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।
- **कौशल विकास और प्रशिक्षण** से जुड़ा है। उद्यमियों और श्रमिकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे उन्हें आधुनिक प्रबंधन, विपणन, वित्तीय योजना और डिजिटल तकनीकों के उपयोग की जानकारी मिल सकेगी।
- **विपणन सुविधाओं का विस्तार** भी अत्यंत आवश्यक है। MSME उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रदर्शनी और व्यापार मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त "मेक इन इंडिया" और "वोकल फॉर लोकल" जैसे अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Cluster Development Programmes)** भी MSME क्षेत्र के विकास में सहायक हो सकते हैं। यदि एक ही क्षेत्र में समान उद्योगों को विकसित किया जाए, तो उन्हें साझा अवसंरचना, तकनीकी सेवाएँ और विपणन सुविधाएँ मिल सकती हैं।

- इसके अलावा **अवसंरचना विकास** पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बिजली, परिवहन, संचार और औद्योगिक पार्क जैसी सुविधाओं का विकास MSME क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- अंततः **नीतिगत स्थिरता और पारदर्शिता** सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरल नियम, डिजिटल प्रक्रियाएँ और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था MSME क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है।
- इन उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने से MSME क्षेत्र की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, उद्यमिता विकास और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत जैसे विकासशील देश में MSME क्षेत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह सीमित पूंजी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। MSME क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कम निवेश में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह उद्योग गरीबी उन्मूलन और आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र पारंपरिक हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों और स्थानीय कौशल को संरक्षित रखने में भी सहायक होता है। वहीं दूसरी तरफ MSME क्षेत्र कई समस्याओं से भी जूझ रहा है, जैसे वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, विपणन कठिनाइयाँ और अवसंरचना का अभाव। इन समस्याओं के कारण इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो जाती है। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाए तो MSME क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति को और अधिक गति दे सकता है।

सरकार ने पिछले वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए ऋण गारंटी योजना, तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम और कौशल विकास योजना जैसी अनेक योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन अभी भी इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

भविष्य में MSME क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित करना आवश्यक होगा। इसके लिए नवाचार, डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स और निर्यात उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना भी आवश्यक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि उचित नीतियों, तकनीकी समर्थन और वित्तीय सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र को मजबूत किया जाए, तो यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि रोजगार सृजन, सामाजिक समावेशन और क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी सुनिश्चित करेगा।

संदर्भ सूची (References)

1. Das, K. (2008). SME sector in India. *Indian Journal of Economics*, 63(4), 45–56.
2. Government of India. (2014). *Annual Report 2013–14*. Ministry of MSME.

3. Kumar, A. (2011). Growth of MSMEs in India. *Economic and Political Weekly*, 46(21), 67–72.
4. Mead, D., & Liedholm, C. (1998). The dynamics of micro and small enterprises. *World Development*, 26(1), 61–74.
5. Reserve Bank of India. (2013). *Report on Trend and Progress of Banking in India*.
6. Schmitz, H. (1995). Small shoemakers and Fordist giants. *World Development*, 23(1), 9–28.
7. Singh, R. (2012). Role of small scale industries in Indian economy. *International Journal of Economic Research*, 3(2), 112–118.
8. Banerjee, A. (2011). *Small and Medium Enterprises in India*. Oxford University Press.
9. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2005). SMEs, growth and poverty. *Journal of Economic Growth*, 10(3), 199–229.
10. Government of India. (2014). *Economic Survey 2013-14*. Ministry of Finance.
11. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2014). *Annual Report 2013-14*. Government of India.
12. Planning Commission. (2013). *Report on MSME Sector in India*. Government of India.